रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड

बनाम

शशि शर्मा और अन्य

(सिविल अपील सं. 9654/2016)

23 सितंबर, 2016

[रंजन गोगोई, प्रफुल्ल सी. पंत और ए.एम. खानविलकर, जे.जे.]

मुआवजा-घातक दुर्घटना-मोटर दुर्घटना में-हरियाणा के तहत आक्रमांक वाला कर्मचारी मृतक सरकारी कर्मचारी नियम, 2006 के आश्रितों को अनुकंपा सहायता-2006 के नियमों के तहत दावेदारों द्वारा प्राप्त राशि को काट क्रमांक के बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा-उच्च न्यायालय क्रमांक कहा कि 2006 के नियमों के तहत भुगतान की गई राशि में कटौती नहीं की जा सकती थी-अपील पर कहा गयाः1988 के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के मामले में, दो प्रमुख सिद्धांत हैं कि यह न्यायसंगत और पर्याप्त होना चाहिए और दावेदारों को कोई दोहरा लाभ नहीं दिया जाना चाहिए-दावेदार 1988 के अधिनियम के तहत 'भुगतान और मजदूरी' विषय के लिए दावा करते हैं, जो आर के तहत प्राप्य है। 5(1)2006 के नियमों के तहत, एक ही शीर्ष के लिए दोगुना भुगतान होगा-1988 के अधिनियम के तहत देय न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण, 2006 के नियमों के तहत मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त या प्राप्य राशि को बाहर करना है-भविष्य में आय और अन्य लाभों के नुकसान के लिए दावा, जो 2006 के नियमों के तहत शामिल नहीं हैं, 1988 के अधिनियम के तहत चलाया जा सकता है-इसी तरह 1988 के उप-नियम (2) से उप-नियम (5) के संदर्भ में दिए गए अन्य लाभ।5 2006 के नियम अप्रभावित रहेंगे और उन्हें लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-मोटर वाहन

अधिनियम, 1988।167 और 168-मृतक सरकारी कर्मचारी नियम, 2006 के आश्रितों को हरियाणा अनुकंपा सहायता -आर. 5.शब्द और वाक्यांशःशब्द 'क्षतिपूर्ति' और 'न्यायसंगत'-का अर्थ।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संयोजन में।

न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में क्षतिपूर्ति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा, इसे मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप अपने परिवार के सदस्य की अचानक और असामयिक मृत्यु के कारण होने वाले संभावित नुकसान के लिए दावेदारों को मुआवजा देने के लिए समझा गया है।[पैरा 15] [505-एफ-जी]

2. क्षतिपूर्ति के निर्धारण के मामले में 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम द्वारा दो प्रमुख सिद्धांत चलते हैं।पहला, मुआवजे का उपाय न्यायसंगत और पर्याप्त होना चाहिए और दूसरा, मुआवजे के पुरस्कार के मामले में दावेदारों को कोई दोहरा लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।1988 के अधिनियम की धारा 168 पहले सिद्धांत को स्पष्ट करती है।उस प्रावधान की उप-धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि मुआवजे की राशि न्यायसंगत होनी चाहिए।"न्यायपूर्ण" शब्द का अर्थ है-निष्पक्ष, पर्याप्त और उचित।यह लैटिन शब्द "जस्टस" से लिया गया है, जिसका अर्थ सही और निष्पक्ष है।हालाँकि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है कि उचित मुआवजा कितनी राशि होगी।[पैरा 15] [505-जी-जे. आई.; 506-ए-बी]

हरियाणा राज्य और अन्र बनामजसबिर अन्य और अन्य। (2003) 7 एससीसी 484:2003 (2) पूरक।एससीआर 245; श्रीमती. सर/वर्मा और अन्य वी.दिल्ली परिवहन

निगम और एएमः(2009) 6 एससीसी 121:2009 (5) एससीआर 1098-पर भरोसा किया गया।

3. आय का नुकसान एक महत्वपूर्ण शीर्ष है जिसके तहत 1988 के अधिनियम के संदर्भ में मुआवजे का दावा किया जाता है।"आय के नुकसान" की मात्रा का घटक, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, "वेतन और मजदूरी" हो सकता है जो अन्यथा मृत कर्मचारी द्वारा अर्जित किया जाता यदि वह मोटर दुर्घटना के कारण हुई चोट से बच जाता।हालाँकि, यदि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियोक्ता द्वारा उस ओर से मुआवजा दिया जाना था, जैसा कि मृत सरकारी कर्मचारी नियमों, 2006 के आश्रितों के लिए हरियाणा अनुकंपा सहायता द्वारा भविष्यवाणी की गई है-अनुदान देने के लिए। मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि के रूप में अनुकंपा वित्तीय सहायता, यह समझ से परे है कि आश्रितों को अभी भी उतनी ही राशि का दावा करने की अनुमति दी जा सकती है जितनी उन्हें 1988 के अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावा बनाए रखने के लिए आय के संभव या संभव नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।[पैरा 16] (506-सी-ई)

4. 2006 का नियम 5 मोटे तौर पर दो पहलुओं से संबंधित है।सबसे पहले, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन और अन्य भत्तों के नुकसान के लिए अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता प्रदान करके मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को मुआवजा देना।नियम 5 का दूसरा भाग मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को भत्तों और रियायतों के माध्यम से मुआवजा देना है-निर्दिष्ट शर्तों पर सरकारी निवास पर कब्जा बनाए रखना, पारिवारिक पेंशन और अन्य भत्ता।जहाँ तक दूसरे भाग का संबंध है, यह अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है जो किसी भी तरह से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित द्वारा प्राप्त की जा सकती है।1988 के अधिनियम के तहत न्यायसंगत

मुआवजे के निर्धारण के लिए दावे की राशि से इसकी कटौती नहीं की जा सकती है। [पैरा 20] [509-ए-सी)

5. दावेदार वैध रूप से 1988 के अधिनियम के तहत नियम 5 के पहले भाग द्वारा कवर किए गए अपकृत्यकर्ता या बीमा कंपनी के खिलाफ मृतक सरकारी कर्मचारी के "वेतन और मजदूरी" के नुकसान के लिए दावा करने के हकदार हैं।हालाँकि, मृतक सरकारी कर्मचारी (हरियाणा राज्य द्वारा नियोजित) के दावेदार या आश्रित नियम 5-"वेतन और भत्ते" के पहले भाग के तहत आने वाले उसी विषय के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें नियोक्ता (राज्य) से 2006 के नियमों के नियम 5 (1) के तहत प्राप्त होते हैं।इसमें यदि मृत कर्मचारी को मोटर दुर्घटना की चोट से बचना था, तो वह रोजगार में बना रहता और अपना नियमित वेतन और भत्ते अर्जित करता।उक्त नियमों की किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी के "वेतन और मजदूरी" के नुकसान के समान शीर्ष के लिए दोगुना भुगतान होगा जो आश्रितों । दावेदारों को उपहार, उदारता या लाभ के स्रोत के अनुदान में निहित है।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 167 में कुछ इसी तरह की स्थिति का उल्लेख किया गया है।[पैरा 21] [509-सी-एफ]

6. 2006 के नियमों के तहत प्राप्य दावे का इसी तरह का वैधानिक बहिष्कार अनुपस्थिति है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दावा न्यायाधिकरण को इस तथ्य से अनजान रहना चाहिए कि मृतक के वेतन और मजदूरी के नुकसान के लिए दावा नियम 5 (1) के तहत अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह वित्तीय सहायता के रूप में नियोक्ता द्वारा पहले ही किया जा चुका है या क्षतिपूर्ति की जाएगी।दावा न्यायाधिकरण को दावे पर निर्णय लेना होता है और मुआवजे की राशि का निर्धारण करना होता है जो उसे उचित लगती है।(पैरा 22) [510-ए-बी)

7. आश्रितों द्वारा प्राप्त होने वाली राशि जो मैं दावेदार हूं, अनुग्रह राशि के रूप में वेतन और भत्तों का सिर प्रदान करती है, इसलिए, दावेदारों को दूसरी बार भुगतान नहीं किया जा सकता है।यह सच है कि 2006 में नियम लागू होंगे यदि सरकारी कर्मचारी की प्राकृतिक मृत्यु में कारण भी मृत्यु हो जाती है।साथ ही, 2006 के नियम स्पष्ट रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को मृत सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के कारण अपकृत्यकर्ता या बीमा कंपनी से समान राशि का दावा करने में सक्षम नहीं बनाते हैं।इसलिए, 1988 के अधिनियम के तहत देय न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि 2006 के नियमों के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त या प्राप्य राशि को "वेतन और अन्य भत्तों" के बराबर मुख्य वित्तीय सहायता के लिए बाहर रखा जाए, जो अंतिम बार मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त की गई थी।[पैरा 22) [510-सी-डी)

8. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नियमों के नियम 5 (1) के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि या भुगतान, "आय की हानि" के शीर्ष के तहत कुल पात्रता है।जहाँ तक आय और अन्य लाभों के भविष्य में वृद्धि के नुकसान का दावा है, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी दुर्घटना में बच गया था, तो उनके द्वारा 1988 के अधिनियम के तहत अपने दावे का पालन किया जा सकता है। क्योंकि, यह 2006 के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।इसी तरह, मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नियम 5 के उप-नियम (2) से उप-नियम (5) के संदर्भ में दिए गए अन्य लाभ, जिनमें पारिवारिक पेंशन, जीवन बीमा, भविष्य निधि आदि शामिल हैं, अप्रभावित रहने चाहिए और कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो किसी भी तरह से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को भुगतान किया जाएगा।[पैरा 22] [510-ई-जी]

9. अपीलकर्ताओं को नियम 2006 के नियम 5 (1) के संदर्भ में मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि की सीमा तक ही सफल होना चाहिए, जो निर्दिष्ट अवधि के लिए मृत कर्मचारी के वेतन और मजदूरी के नुकसान के बराबर वित्तीय सहायता है।[पैरा 23] [510-एच; 511-ए)

10. उच्चतम न्यायालय की समन्वय पीठों (दो न्यायाधीशों की) के बीच एक ओर एक तरफ भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का मामला और दूसरी तरफ ओर हेलेन सी.रेबेल्लो और पेट्रीसिया जे.महाजन के मामले में राय का कोई टकराव नहीं है।पूरे निर्णय में कोई अवलोकन नहीं मिला जाता है।हेलेन सी.रेबेल्लो और पेट्रीसिया के मामलों में उक्ति की शुद्धता पर संदेह किया है।[पारस 8 और 14] [497-ई; 505-ई)

* * हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) और अन्य वी.महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और एएमः1999 (1) एससीसी 90:1998 (1) पूरक।एस. सी. आर. 684; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनामसरोज देवी 2012 (टी) पीएलआर 761; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी बनाम.श्रीमती. संतुश 2010 (4) पीएलआर 780; भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम कांता अग्रवाल (श्रीमती) और अन्य 2008 (11) धारा 366:2008 (10) एससीआर 165; गोबाल्डमोटर सर्विस लिमिटेड बनाम आर. एम. के. वेलुस्वामी 1962 (1) एस. सी. आर. 929; शेखुपुरा 'फ़्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड'।एमजेआर/हर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस कं. 1971 (1) एससीसी 785; विमल अन्य और अन्य। वी.किशोर दान और अन्य 2013 (7) एस. सी. सी. 476; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम देव पटोडी और अन्य । 2009 (13) एससीसी 123:2009 (8) एस. सी. आर. 791; * * * यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।पेट्रीसिया जीन महाजन और अन्य 2002 (6) एससीसी 281:2002 (3) एस. सी. आर. 1176-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

21)12 (1) पी. एल. आर. 761	संदर्भित	पैरा 6
2010 (4) पी. एल. आर. 780	संदर्भित	पैरा 6
2002 (3) एस. सी. आर. 1176	संदर्भित	पैरा 6
2008 (10) एस. सी. आर. 165	संदर्भित	पैरा 7
1962 (1) एस. सी. आर. 929	संदर्भित	पैरा 7
1911 (1) एस.सी.सी 785	संदर्भित	पैरा 7
2013 (7) धारा 476	संदर्भित	पैरा 7
2009 (8) एस. सी. आर. 791	संदर्भित	पैरा 7
1998 (1) पूरक।एससीआर 684	संदर्भित	पैरा 8
2003 (2) पूरक।एससीआर 245	भरोसा किया	पैरा 15
2009 (5) एससीआर 1098	भरोसा किया	पैरा 15

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9654/2016

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, के चंडीगढ़ की एफ ए ओ नंबर 503/2012 मे पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.02.2012 से

साथ

सी.ए.संख्या 9655, 9657, 9659, 9661, 9663-9664,9666, 9669, 9671,9677,9674,9673, 9672, 9675, 9670, 9667-9668, 9665,9662,9660,9658,9656 और 9676 of 2016 ।

ध्रुव मेहता, महाबीर सिंह, पल्लव सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता।, Ms.Prerna मेहता, सुश्री अनुपमा डलमर्वे, यादव नरेंद्र सिंह, गौरव जैन, सतीश कुमार, विष्णु मेहरा,

सुश्री साक्षी मित्तल, सुश्री मंजीत चावला, अभिषेक गोला, निखिल जैन, गगनदीप शर्मा, सुश्री प्रीति सिंह, रवींद्र केशवराव अदसुरे, भारत भूषण, राकेश विशन, गौरव जैन, डॉ. मीरा अग्रवाल, रमेश चंद्र मिश्रा, के.के.मोहन, अभिषेक गोला, विरेश बी. सालियार्या, सुश्री मीनाक्षी मिधा, चंदर शेखर अशरी, अनिल नाग, रवि मेहरोत्रा, आर. के. सिन्हा, (भास्कर वाई. कुलकर्णी के लिए), अनिल कुमार तांडले, करण कपूर, माणिक सिद्दीकी, राकेश दहिया, राज कुमार, देवाशीष भरुका, बिश्नोई, वैभव, सुश्री रानी भरुका, अनिल हुड्डा, अंकित गुप्ता, कौशल यादव, निखिल गोयल, आशुतोष, सुश्री तवीशी चंद्र, करण चौधरी, सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय, दिनेश वर्मा, रजत शर्मा, सुभाशीष भौमिक, डॉ. सुधीर बिस्ला, सुश्री सुर्निंत्रा बिस्ला, कमल मोहन गुप्ता, रविंदर कुमार, (श्रीमती शील सेठी के लिए),अधिवक्ता । उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश ए.एम.खानविलकर,जे. द्वारा पारित किया गया:-

1. विलंब क्षमा किया गया।

2. स्वीकृति दी गई।

3. इन मामलों को 71 अक्टूबर, 2015 के आदेश की शर्तों के तहत तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया है।इस आदेश में कोई विशिष्ट प्रश्न तैयार नहीं किया गया है जिसका उत्तर वृहद पीठ द्वारा दिया जाना है।

4. प्रमुख अपील में 13 फरवरी, 2013 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी गई है।वह अपील प्रत्यर्थियों द्वारा (एस. विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या.14312/2013 से उत्पन्न अपील में) एम. ए. सी. टी. मामले No.136dated 3 नवंबर 2011 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जींद के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।उक्त प्रत्यर्थीगण ने जींद में जनरल अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने 24 से 1 अक्टूबर 2010 को एक मोटर

दुर्घटना के कारण डॉ. अश्विनी शर्मा की मृत्यु के बाद एक दावा याचिका दायर की थी। उस दुर्घटना में कारित चोटों के कारण दम तोड़ दें।न्यायाधिकरण ने दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।मृतक शर्मा के आश्रित दावेदारों को मुआवजे के रूप में रु. Dr.Ashwini की राशि प्रदान की गई थी, जिसमें दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को दावेदारों को निर्णय में निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा और अन्य स्रोतों में प्राप्त मुआवजे की राशि के भाग लेने में पीड़ित होने के कारण दावेदारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।उच्च न्यायालय ने रीलेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य एफ.ए.ओ. संख्या.1322/2010 के मामले में 21 दिसंबर, 2012 को उसी उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए दावेदारों के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मृत सरकारी कर्मचारी नियम, 2006 (इसके बाद "2006 के नियम" संदर्भित) के आश्रितों को हरियाणा अनुकंपा सहायता के तहत मृतक के आश्रितों द्वारा प्राप्त राशि को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा से नहीं काटा जा सकता है।उस निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में प्रत्यर्थियों की अपील की अनुमति दीः

> "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रु.89,24,604/- (रु. I,00,957/- - रु.15,143 का 15% = रु.85,814/- - रु.28,605/- का 1/3) =रु.57,209 x 12=रु.6,86,508/- x 13 = 89,24,604) निर्भरता की हानि के लिए, रु. मैं कंसोर्टियम के नुकसान के लिए 5,000/- रु 1 अपीलकर्ता, रु. 15,000/- संपत्ति के नुकसान के लिए, रु. 10,000/ - अंत्येष्टि व्यय के लिए और परिवहन व्यय के लिए रु. 5,000/-, याचिका की तारीख से भुगतान की तिथि तक मुआवजे के बढ़े हुए हिस्से के लिए 7.5% की दर से ब्याज के

साथ कुल मिलाकर रु. 89,60,604/- की राशि। लागू ब्याज दर और ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए बंटवारे के तरीके की पुष्टि की गई है।"

5. उच्च न्यायालय ने समान सुनवाई के लिए सूचीबद्ध संबंधित सहयोगी मामलों में 2006 के नियमों के अनुसार दावेदारों द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि की कटौती को अस्वीकार करने के लिए समान तर्क अपनाया है।अपीलकर्ताओं-बीमा कंपनियों द्वारा इन अपीलों में एकमात्र तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने 2006 के नियमों के तहत संबंधित दावेदारों द्वारा प्राप्त राशि की कटौती को ।988 के अधिनियम के तहत दावेदारों को देय मुआवजे की राशि से अलग करते हुए कानूनी रूप से गलती की है।

6. चूँकि उच्च न्यायालय ने पूर्णिमा के मामले (ऊपर) में उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है, इसलिए उस निर्णय का पहला विज्ञापन देना उचित होगा।यह निर्णय एक बड़ी पीठ के संदर्भ में दिया गया था, एक प्रश्न पर जिसे अपीलकर्ताओं - बीमा कंपनियों द्वारा वर्तमान अपीलों में भी प्रचारित किया गया है, सिंह के परस्पर विरोधी निर्णयों के मद्देनजर: ओरिएंटल के मामले में उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंश्योरेंस कंपनी बनाम सरोज देवी 2012 (1) पीएलआर 761 और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम संतोष के मामले में 2010 (4) पीएलआर 780 खण्ड पीठ द्वारा विचार किया गया प्रश्न थाः "चाहे वह क्षतिपूर्ति हो। मृत सरकारी कर्मचारियों के प्रतिवादियों को हरियाणा अनुकंपा सहायता नियम, 2006 (या अन्यथा) के तहत सरकार से प्राप्त कुल मुआवजे में से कटौती की जानी है, जो सरकार द्वारा अनुग्रह राशि के माध्यम से वित्तीय लाभों की गणना करते समय मृतक के आश्रितों को देय है, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है? खण्ड पीठ ने 2006 के नियमों की योजना और आशय का विश्लेषण किया और कहा कि उक्त नियम हरियाणा के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं; इन नियमों को न केवल संपत्ति बल के रूप में माना जाना चाहिए, बल्कि इन्हें

विधानमंडल द्वारा अधिनियमित क़ानून के बराबर माना जाना चाहिए; इन नियमों का उद्देश्य मृतक के परिवार को नौकरी में कर्मचारी की मृत्यु (न केवल मोटर दुर्घटना के कारण) या जो लापता हो जाता है या जो गुम हो जाता है, के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाई से उबरने में सहायता करना है।मृतक कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में पता नहीं है; कर्मचारी के आश्रितों को दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता का मोटर दुर्घटना के कारण कर्मचारी की मृत्यु के कारण से कोई संबंध नहीं है।दूसरे शब्दों में काम पर रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर, चाहे वह प्राकृतिक मृत्यु हो या बीमारी के कारण या अन्यथा, 2006 के नियम लागू हो जाएंगे; और।जिसके परिणामस्वरूप मृतक कर्मचारी का परिवार नियोक्ता से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार है।डिवीजन बेंच ने माना कि 2006 के नियमों में अभिनिर्धारित वित्तीय सहायता की योजना एक सेवा लाभ है जो मृतक के आश्रितों को प्राप्त होता है और यह सेवा मामले/मृतक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप कर्मचारी को दिए गए लाभ के क्षेत्र में है।मृतक के आश्रितों को मिलने वाला लाभ पेंशन/परिवार पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार दी जाने वाली बढ़ी हुई पेंशन की प्रकृति में है, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पेंशन आमतौर पर कर्मचारी द्वारा मेधावी, लंबी और वफादार सेवा के लिए दी जाती है। डिवीजन बेंच हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य और यूनाइटेड इंडियाइंश्योरेंस कंपनी बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन और अन्य मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा कर रही है। यह माना गया कि अपकृत्यकर्ता या बीमा कंपनियां अपनी देनदारी को माफ या कम नहीं करवा सकतीं क्योंकि मृतक के परिवार को मृतक की मृत्यु के कारण वैकल्पिक स्रोत (नियोक्ता) से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इसने अभिनिर्धारित किया कि क्षतिपूर्ति की राशि से कटौती स्वीकार्य है यदि दावेदार को कारित चोटों के मेंिणामस्वरूप लाभ प्राप्त होता है जो

अन्यथा वह हकदार नहीं होता; और उन मामलों को शामिल नहीं करता है जब प्राप्त भुगतान दुर्घटना से होने वाली चोट में निर्भर नहीं होता है।कि 2006 के नियमों के तहत प्राप्त सहायता केवल मोटर दुर्घटना से उत्पन्न कर्मचारी की मृत्यु पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार, इसका मृत्यु के तरीके से कोई संबंध नहीं है। तदनुसार, डिवीजनबेंच ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय मुआवजा राशि की गणना करते समय बीमा कंपनी 2006 के नियमों के तहत आश्रितों को दी गई राशि में कटौती का दावा करने की हकदार नहीं है।

7. दूसरी ओर, बीमा कंपनियों ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम कांता अग्रवाल (श्रीमती) अन्य 2008 (11) एससीसी 366 मामले में इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। उस मामले में अपीलकर्ता की याचिका का प्रतिवाद करने के लिए कि दावेदारों को उसके पति की मृत्यु के कारण अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है "अनुकंपा नियुक्ति के कारण वेतन राशि के रूप में और साथ ही उसे प्रदान किया गया निवास कटौती योग्य था, इस अदालत द्वारा स्वीकार किया गया है; और मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय न्यायसंगत मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय इस तरह से कटौती की गई थी। गोबल्ड मोटर सर्विस लिमिटेड बनाम आर.एम.के.वेलुस्वामी 1962 (1) एससीआर 929 =एआईआर 1962 एससी । में तीन जजों की बेंच के आदेश पर भी भरोसा किया गया है, जो बीमा कंपनी के अनुसार, नियोक्ता से मृतक के आश्रितों को प्राप्त मुआवजे जैसे लाभों में कटौती की अनुमति देता है। शेखूपुरा ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड बनाम नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी 1971(1) एससीसी 785 के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया गया है; विमल कंवर और अन्य के मामले में अन्य दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया गया है। बनाम किशोर दान एवं अन्य 2013 (7) एससीसी 476 इसके बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में इस न्यायालय

के दो न्यायाधीशों की पीठ के दूसरे फैसले पर भरोसा किया जाता है। लिमिटेड बनाम देव पटोदी और अन्य 2009 (13)एससीसी 123। मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय उचित मुआवजे को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों पर विचार करने के लिए । संक्षेप में, बीमा कंपनियों का तर्क यह है कि दावेदारों को मुनाफाखोरी करने और अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण एक ही मद में दोहरा लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्हें "आय की हानि" हुई ।

8. बीमा कंपनियों के उपरोक्त उल्लिखित रुख के अलावा एक अन्य आनुषंगिक प्रश्न जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या इस अदालत की (दो न्यायाधीशों की) समन्वय पीठों के बीच, एक ओर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (ऊपर) के मामले में और दूसरी ओर हेलेन सी. रेबेलो और पेट्रीसिया (ऊपर) के मामले में कोई परस्पर विरोधी राय है।

9. इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ के गोबाल्ड मोटर सर्विस लिमिटेड (ऊपर) के मामले में निर्णय का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है और हेलेन के मामले (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अलग किया गया है। कि, गोबाल्ड मोटर के मामले में कथन घातक दुर्घटना अधिनियम,1855 की धारा 1 और 2 के संदर्भ में देय नुकसान की मात्रा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में था,जिन्हें भौतिक रूप से अलग माना जाता है। दूसरी ओर,मोटर वाहन अधिनियम,1939 के प्रावधान ने मुआवजे की राशि की गणना की गुंजाइश को बढ़ा दिया है।हेलेन के मामले में अदालत ने कहा कि गोबाल्ड के मामले में अवलोकन मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में मृतक के आश्रितों द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त राशि की कटौती का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है।यहाँ तक कि शेखुपुरा परिवहन (उपरोक्त) के मामले में निर्णय को भी नमूने पर समझाया और अलग किया गया है।

10. प्रश्न यह हैःक्या हेलेन के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विशेष रूप से पैराग्राफ 32 से 35 में बताए गए सिद्धांत पर संदेह किया जा सकता है?उस मामले में अदालत से जवाब देने के लिए कहा गया था कि क्या मोटर वाहन अधिनियम (उस मामले में 1939 के अधिनियम की धारा 110बी, 92ए और 92बी, जो 1988 के अधिनियम की धारा 168,140 और 141 के अनुरूप है) के प्रावधानों के तहत देय मुआवजे की राशि से मृतक के आश्रितों द्वारा "जीवन बीमा नीति" के लिए प्राप्त राशि की कटौती को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।पैराग्राफ 32 से 35 इस प्रकार हैं:

> "32.जहाँ तक सामान्य कानून के तहत नुकसान का अनुमान लगाने के सामान्य सिद्धांत का संबंध है, यह तय किया जाता है कि आर्थिक नुकसान का पता केवल एक तरफ संतुलन बनाकर लगाया जा सकता है, भविष्य के आर्थिक लाभों के दावेदार के लिए नुकसान जो उसे अर्जित होता, लेकिन मृत्यु के साथ "आर्थिक लाभ" के लिए जो मृत्यु के कारण उसे स्रोत से आता है।दूसरे शब्दों में, यह मृत्यु के कारण दावेदार के नुकसान और लाभ का संतुलन है।लेकिन इसे अपना रंग उस हद तक बदलना होगा जिस हद तक अधिनियम करना चाहता है। इस प्रकार, इसकी व्याख्या मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के आलोक में की जानी चाहिए।यह स्पष्ट है।जिसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उसका अधिनियम दावेदार को केवल आकस्मिक चोट या मृत्यु के कारण मुआवजा देता है।किसी अन्य मृत्यु के कारण नहीं।इस प्रकार, इस अधिनियम के तहत अर्जित होने वाले आर्थिक लाभ को आकस्मिक मृत्यु से संबंधित समझ लेना होगा।मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय मुआवजा दावेदार को आकस्मिक चोट या

मृत्यु के कारण दिया जाता है, न कि मृत्यु के अन्य रूपों के कारण। यदि आत्महत्या द्वारा प्राकृतिक मृत्यु या मृत्यु होती है, गंभीर बीमारी, जिसमें दुर्घटना द्वारा मृत्यु भी शामिल है, ट्रेन, हवाई उड़ान के माध्यम द्वारा, जिसमें मोटर वाहन शामिल नहीं है, तो यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं आता है। इस प्रकार, इस अधिनियम के तहत मुआवजे की गणना के लिए हानि और लाभ के सामान्य कानून के तहत सामान्य सिद्धांत का अनुप्रयोग इस प्रकार की चोट या मृत्यु द्वारा संबंधित होना चाहिए, अर्थात।, आकस्मिक।यदि किसी भी स्रोत से "आर्थिक लाभ" शब्दों की व्याख्या इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की मृत्यु के रूप में की जाती है, तो यह दावेदार को प्रदान किए गए सभी संभव लाभों को कम कर देगा और कानून की भावना के विपरीत होगा।यदि मृत्यु के परिणामस्वरूप "आर्थिक लाभ" का अर्थ है मृत्यु के सभी रूपों के तहत आने वाला आर्थिक लाभ, तो इसमें सभी चल, अचल, शेयर, बैंक खाते, नकद और किसी भी अनुबंध के तहत प्राप्त होने वाली प्रत्येक राशि शामिल होगी।दूसरे शब्दों में, सभी वंशानुगत परिसंपत्तियाँ, जिसमें मृतक की इच्छा भी शामिल है, यह मृतक द्वारा दावेदार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और विधायिसंभव के इरादों दोनों को समाप्त कर देगा।इस तरह की अधिनियम से, यातना का शिकार होने वाला अपने गलत कार्य या लापरवाही के बावजूद, जो मृत्यु में योगदान देता है, मनुष्य के मामलों में कोई दायित्व या अल्प दायित्व नहीं होगा।, लाभ की व्याख्या की जानी चाहिए जो आकस्मिक मृत्यु के परिणामस्वरूप होता है और आकस्मिक मृत्यु के कारण नुकसान होता है।इस प्रकार।वर्तमान

अधिनियम के तहत, जो भी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है) दावेदार का, किसी भी स्रोत से, केवल ई का अर्थ होगा जो दावेदार के पास आकस्मिक मृत्यु के कारण आता है, न कि मृत्यु के अन्य रूपों के कारण।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन धारा 110 के तहत स्वयं किया गया है, जैसा कि धारा में कहा गया हैः

".....मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से।

33. इस प्रकार, इसमें वह शामिल नहीं होगा जो दावेदार को अन्य प्रकार की मौतों के कारण प्राप्त होता है, जो उसे आकस्मिक मृत्यु के अलावा भी प्राप्त होता।इस प्रकार, गुसच आर्थिक लाभ का आकस्मिक मृत्यु से कोई संबंध नहीं होगा जिसके लिए मुआवजे की गणना की जाती है।ए) आकस्मिक मृत्यु के कारण प्राप्त या प्राप्य राशि) लेकिन जो दावेदार के पास अन्यथा भी आती, उसे एच "आर्थिक लाभ" नहीं माना जा सकता था।कटौती के लिए उत्तरदायी।हालांकि, जहां नियोक्ता अपने कर्मचारी का बीमा करता है, दुर्घटना से उत्पन्न चोट या मृत्यु के खिलाफ, ऐसी घटना होने पर इस तरह के बीमा से प्राप्त कोई भी राशि कटौती के लिए उत्तरदायी राशि हो सकती है।हालाँकि, हमारे कानून ने धारा 95 के प्रावधान के माध्यम द्वारा ऐसी आकस्मिकता पर ध्यान दें है।इसके तहत बीमाकर्ता के दायित्व को किसी कर्मचारी के रोजगार से उत्पन्न होने वाली चोट या मृत्यु के संबंध में शामिल नहीं किया गया है।

34. यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक ही घटना के होने के लिए दावेदार को दो स्रोतों से दो बार लाभ नहीं हो सकता है।इस प्रकार, इद्वारा या तो विधायिका की बुद्धि के माध्यम द्वारा या कटौती के माध्यम द्वारा हानि और लाभ के सिद्धांत के माध्यम द्वारा बाहर रखा गया है, ताकि एक ही लेनदेन द्वारा उत्पन्न होने वाले दावेदार को दो बार लाभ न मिले।, एक ही घटना।यहाँ दोनों स्रोतों में दर्ज करना महत्वपूर्ण है।, या तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत या नियोक्ता से, दावेदार द्वारा प्राप्य मुआवजा या तो वैधानिक है या नियोक्ता की प्रतिभूति के माध्यम से अपने कर्मचारी के लिए सुरक्षित है, लेकिन दोनों ही मामलों में वह अपने योगदान के बिना राशि प्राप्त करता है। इस प्रकार किसी के श्रम या किसी के धन, बचत में योगदान से अर्जित राशि।आदि या तो अपने लिए या अपने परिवार के लिए जिसे ऐसा व्यक्ति कानून के तहत जानता है, उसे अपने उत्तराधिकारियों के पास जाना पड़ता है।उनकी मृत्यु के बाद या तो उत्तराधिकार द्वारा या वसीयत के तहत केवल किसी की आकस्मिक मृत्यु के कारण "आर्थिक लाभ" कहा जा सकता है।यह निश्चित रूप से एक आर्थिक लाभ है, लेकिन यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से न्यायसंगत या संतुलित हो सकता है। इन दोनों राशियों के बीच कोई संबंध नहीं है।दूर से भी नहीं।एक अनुबंध के नुकसान और लाभ की राशि को दूसरे अनुबंध के नुकसान और लाभ पर कैसे लागू किया जा सकता है।इसी तरह, कैसे एक अधिनियम के तहत प्राप्य राशि का किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित राशि के साथ कोई संबंध है।हानि और लाभ का सिद्धांत एक ही क्षेत्र के भीतर

एक ही स्तर पर होना चाहिए, निश्चित रूप से, इसके विपरीत अनुबंध या कानून के किसी भी प्रावधान के अधीन।

35. मोटे तौर पर, हम भविष्य निधि की प्राप्ति की जांच कर सकते हैं जो एक कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के कार्यकाल के दौरान किए गए योगदान से एक आस्थगित भुगतान है।आकस्मिक मृत्यु के बावजूद कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी इस राशि को प्राप्त करने के हकदार हैं।यह राशि सुरक्षित है, प्राप्त होना निश्चित है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राशि अनिश्चित है और केवल घटना के घटित होने पर ही प्राप्त की जा सकती है।, दुर्घटना, जो शायद न हो!बिल्कुल भी नहीं।इसी तरह, एक कर्मचारी द्वारा अपनी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाली सेवा शर्तों के संदर्भ में सेवा में अपने योगदान के रूप में अपने परिवार के लाभ के लिए पारिवारिक पेंशन भी अर्जित की जाती है।आकस्मिक मृत्यु के अलावा भी उत्तराधिकारियों को पारिवारिक पेंशन मिलती है।दो के बीच कोई कोरलेशन नहीं है। इसी तरह, जीवन बीमा नीति या तो बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के उत्तराधिकारियों द्वारा बीमाकर्ता के साथ अनुबंध के कारण प्राप्त की जाती है, जिसके लिए बीमित व्यक्ति प्रीमियम के रूप में योगदान करता है।यह बीमित व्यक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है यदि वह सभी प्रीमियम का भुगतान करने के बाद परिपक्वता तक जीवित रहता है।मृत्यु के मामले में बीमाकर्ता उत्तराधिकारी को राशि का भुगतान करने के लिए क्षतिपूर्ति करता है, फिर से भुगतान किए गए प्रीमियम के अनुबंध के संदर्भ में।पुनः, यह राशि दावेदार द्वारा किसी आकस्मिक मृत्यु के कारण नहीं बल्कि

बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण प्राप्त की जा सकती है।मृत्यु केवल अनुबंध के संदर्भ में आकस्मिक या आकस्मिकता है, राशि प्राप्त करने के लिए।इसी तरह कोई भी नकदी, बैंक शेष राशि, शेयरों में सावधि जमा आदि, हालांकि सभी धन संबंधी लाभ हैं जो किसी की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी का किसी अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली राशि के साथ कोई संबंध नहीं है जो केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण होती है।ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम की परिधि के भीतर कैसे आ सकती है जिसे कटौती के लिए उत्तरदायी "आर्थिक लाभ" कहा जा सकता है।जब हम हानि और लाभ के सिद्धांत की तलाश करते हैं, तो यह उनके बीच एक समान और एक ही समतल संबंध पर होना चाहिए, न कि जिसके साथ किसी भी कोरलेशन की कोई झलक न हो।बीमित व्यक्ति (मृतक) अपने स्वयं के धन का योगदान करता है जिसके लिए उसे वह राशि प्राप्त होती है जिसका दुर्घटना के कारण उसकी लापरवाही के लिए अपकृत्यकर्ता के खिलाफ संगणित मुआवजे के लिए कोई कोरलेशन नहीं है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम के तहत मुआवजे के रूप में प्राप्य राशि चोट या मृत्यु के कारण होती है, जिसमें कोई योगदान नहीं किया जाता है, तो बीमित व्यक्ति के योगदान के माध्यम द्वारा प्राप्त राशि का फल मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्राप्य राशि में द्वारा कैद्वारा काटा जा सकता है।इस अधिनियम के तहत राशि बिना किसी योगदान के प्राप्त होती है।जैसा कि हमने कहा है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय मुआवजा सांविधिक है जबकि

जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्य राशि संविदात्मक है।"(जोर दिया गया)

11. इस निर्णय ने सामान्य कानून के तहत नुकसान का अनुमान लगाने के लिए सामान्य सिद्धांत के अनुप्रयोग के संबंध में कानूनी स्थिति का विश्लेषण किया है।इसने अधिनियम (1951 का 3) द्वारा अपने संशोधन से पहले और फिर घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों के बीच अंतर करने वाली विशेषताओं को भी नोट किया है।इसके बाद यह मिला गया कि गोबाल्ड के मामले में अदालत ने अंग्रेजी निर्णयों पर निर्भरता रखते हुए इस मुद्दे का फैसला किया-क्योंकि उस समय लागू होने वाले प्रावधान अंग्रेजी घातक दुर्घटना अधिनियम, 1846 की धारा 9 के समान थे।अदालत को न तो मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत निर्धारण करने के लिए कहा गया था और न ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की कटौती को न्याय हित माना गया था। अदालत ने कहा कि 1939 के अधिनियम की धारा 110-बी (1988 के अधिनियम की धारा 168 के अनुरूप) की भाषा घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा । ए से अलग है।इसने अभिनिर्धारित किया कि 1939 के अधिनियम की धारा 110-बी न्यायाधिकरण को मुआवजे का निर्धारण करने का अधिकार देती है, जो उसे "न्यायसंगत" प्रतीत होता है।अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रावधान मुआवजे के निरोध की गुंजाइश को बढ़ाता है, जो न तो भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत अनुमेय है और न ही अंग्रेजी घातक दुर्घटना अधिनियम, 1846 के तहत अनुमेय है।इसके बाद अदालत ने इस आयोग के निर्णयों का विश्लेषण किया और कहा कि 1939 के अधिनियम की भाषा में जानबूझकर विचलन किया गया है, जिससे न्यायाधिकरण पर व्यापक विवेकाधिकार रखने के विधायिका के इरादे का पता चलता है।इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावेदार को देय मुआवजे का निर्णय लेते

समय पिछले कानून पर लागू सिद्धांतों पर आधारित निर्णयों को लागू नहीं किया जा सकता है।पैराग्राफ 28 में, अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

> "28 ..... इससे पता चलता है कि "न्यायसंगत" शब्द को जानबूझकर 1939 के अधिनियम की धारा 110 बी में मुआवजे की गणना में विचार को व्यापक बनाने के लिए लाया गया था, जिसमें निश्चित रूप से कटौती का प्रश्न शामिल होगा, यदि कोई हो।यह हमें एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाता है कि अंग्रेजी घातक दुर्घटना अधिनियम, 1846 के तहत और भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत पहले के निर्णयों द्वारा मुआवजे की गणना का सिद्धांत, किसी भी मार्गदर्शक शब्दों की अनुपस्थिति में में प्रतिबंधात्मक प्रकृति का था, क्योंकि अदालतों ने सामान्य लॉफ्लॉस और गेन पर सामान्य सिद्धांत लागू किया था, लेकिन यह 1939 के अधिनियम की धारा 110-बी के तहत विचारों पर लागू नहीं होगा, जो दावेदार को बेहतर न्यायाधीश देने के लिए विवेकाधिकार को बढ़ाता है, मुआवजे की गणना नहीं करता है, यह देखने के लिए कि क्या उचित है।इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालयों के सभी निर्णय, जो इन दोनों अधिनियमों के सिद्धांतों पर उनकी व्याख्या पर आधारित हैं।,अंग्रेजी 1846 अधिनियम और भारतीय 1855 अधिनियम को यह ठहराने के लिए कि कटौती वैध थी, बरकरार नहीं रखा जा सकता है।जैसा कि हमने ऊपर देखा है, गोबाल्ड मोटर सेवा में इस अदालत के निर्णय के संदर्भ में भी निर्णय जहां न तो प्रश्न उठाया गया था और न ही निर्णय लिया गया था और यह मामला भी, 1855 के अधिनियम के तहत होने के कारण, सेवा में दबाव नहीं डाला जा सकता है।इस प्रकार, ये

न्यायालय घातक दुर्घटना अधिनियम की भाषा की सीमा के आधार पर मुआवजे की गणना में एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या देकर एक त्रुटि के दायरे में आ गए, क्योंकि उन्होंने 1939 के अधिनियम में भाषा के परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा और धारा 110-बी के तहत न्यायाधिकरण के विवेकाधिकार को व्यापक बनाने पर विचार नहीं किया। "न्यायपूर्ण" शब्द, इसके नामकरण के रूप में।एक बड़े परिधीय क्षेत्र में समानता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता को दर्शाता है। विस्तार, निश्चित रूप से, मनमाना नहीं हैःयह विवेक द्वारा प्रतिबंधित है जो उचित, उचित और न्यायसंगत है, यदि यह अधिक हैः इसे अनुचित, अनुचित, गैर-न्यायसंगत, न्यायसंगत नहीं कहा जाता है।इस प्रकार, न्यायाधिकरण के व्यापक विवेकाधिकार का यह क्षेत्र उक्त सीमाओं और इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या कानून के बल वाले किसी अन्य प्रावधान के तहत सीमाओं के भीतर होना चाहिए।"(जोर दिया गया)

12. इस निर्णय में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है कि नुकसान का अनुमान लगाने के लिए सामान्य कानून के तहत सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग को मोटर वाहन अधिनियम. आगे के तहत मुआवजे की गणना के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जो कि किसी भी स्रोत से "आर्थिक लाभ" मोटर दुर्घटना के कारण होने वाली चोट या मृत्यु से संबंधित होना चाहिए।लिया गया दृष्टिकोण, 1939 के मोटर वाहन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का सही विश्लेषण और व्याख्या है, और इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संबंधित प्रावधानों पर उचित रूप से लागू होना चाहिए।पेट्रीसिया के मामले (उपरोक्त) में दो न्यायाधीशों की पीठ के बाद के निर्णय में इस सिद्धांत को दोहराया गया है, जिसमें बीमा कंपनी के "सामाजिक सुरक्षा मुआवजे" और "जीवन बीमा पॉलिसी" के

माध्यम से मृतक के आश्रितों द्वारा प्राप्त राशि में कटौती करने के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया है।

13. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (उपरोक्त) के मामले में यह प्रतीत हो सकता है कि दावेदार को उसके पति की मृत्यु के कारण किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आर्थिक लाभ की कटौती की अनुमति देने के लिए एक प्रस्थान किया गया है।हालाँकि, उक्त निर्णय के निकट विश्लेषण पर, दो पहलू प्रमुख हो जाते हैं।सबसे पहले, अपीलकर्ता बोर्ड की शिकायत यह थी कि दावेदारों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जो अभी भी लंबित थी। हालांकि, उसी फैसले के खिलाफ बोर्ड द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता की शिकायत अनिवार्य रूप से उसकी अपील को खारिज करने में उच्च न्यायालय के अनुचित दृष्टिकोण के बारे में थी।इसे रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 13 में दिए गए अवलोकन से समझा जा सकता है। रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैरा 14 में मिला गए अवलोकन से यह देखा गया है कि उच्च अदालत के फैसले को स्पष्ट रूप से अस्थिर माना गया है।इसे अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अस्वीकार करने के रूप में समझा जाना चाहिए, हालांकि मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए दावेदारों द्वारा दायर प्रति अपील उसके समक्ष लंबित थी।दूसरा पहलू यह है कि अदालत ने पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने और उनके बीच लंबे समय से लंबित आई. आई. टी. (14 वर्ष) को शांत करने के लिए, जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष खर्च किए गए दावेदारों की अपील का निपटारा करना शामिल है, सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए एक आदेश किया।इसका पता पैराग्राफ 13 और 14 से लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:

> "13.प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया और अतिरिक्त रूप से निवेदन कि प्रतिवादी । की अपील लंबित है।सामान्य

तौर पर, जब दो अपीलों को सामान्य निर्णय के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, तो दोनों अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक ही पीठ द्वारा की जानी चाहिए।लेकिन हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि दावेदार को मृत्यु या चोट के कारण मिलने वाले लाभों पर मुआवजे का निर्धारण करते समय विधिवत विचार किया जाना चाहिए।यह बताया गया है कि प्रतिवादी 1 को 4,700/- रुपये बर्बाद हो रहे हैं और उसे एक निवास प्रदान किया गया है और वास्तव में दुर्घटना के तुरंत बाद अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी।

"14. ऊपर जो कहा गया है उसे देखते हुए, उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर है।हालाँकि, दुर्घटना 14 साल से अधिक समय पहले हुई थी और नए सिरे से विचार के लिए मामले को न्यायाधिकरण को वापस भेजना वांछनीय नहीं होगा।इस न्यायालय के दिनांकित 1-11-2004 आदेश के अनुसार पाँच लाख रुपये की राशि जमा की गई है।हमारा विचार है कि पृष्ठभूमि के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित और उचित है कि पहले से जमा किए गए पांच लाख रुपये की राशि को दावेदारों द्वारा मृतक की मृत्यु से संबंधित दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।यह न्यायाधिकरण का काम है कि वह सावधि जमा की मात्रा और दावेदारों को जारी की जाने वाली राशि तय करे।"(जोर दिया गया)

14. इस प्रकार समझा जाए तो, यह हेलेन सी. रेबेलो और पेट्रीसिया 'स्केज़ में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की तुलना में एक विपरीत दृष्टिकोण लेने का अधिकार नहीं है।

वास्तव में रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैरा 11 में हेलेन सी. रेबेलो के मामले के पैराग्राफ 32 से 34 को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया गया है।हेलेन सी. रेबेलो और पेट्रीसिया के मामले में कथन की शुद्धता पर संदेह करने के लिए पूरे निर्णय में कोई अवलोकन नहीं मिला गया है।

15. जो भी हो, 1988 के अधिनियम में क्षतिपूर्ति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।व्याख्यात्मक प्रक्रिया से, यह समझा गया है कि मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप अपने परिवार के सदस्य की अचानक और असामयिक मृत्यु के कारण होने वाले संभव नुकसान के लिए दावेदारों को मुआवजा देना है।क्षतिपूर्ति के निरोध के मामले में 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम द्वारा दो प्रमुख सिद्धांत चलते हैं।पहला, मुआवजे का उपाय न्यायसंगत और अपर्याप्त होना चाहिए और दूसरा, पुरस्कार के मामले में दावेदारों को कोई दोहरा लाभ नहीं जाना चाहिए।मुआवजे के लिए।1988 के अधिनियम की धारा 168 पहले सिद्धांत को स्पष्ट करती है।उस प्रावधान की उप-धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि मुआवजे की राशि न्यायसंगत होनी चाहिए। "जस्ट" शब्द का अर्थ है-निष्पक्ष, पर्याप्त और (उचित)। यह लैटिन शब्द "जस्टस" से लिया गया है, जिसका अर्थ सही और निष्पक्ष है।हरियाणा राज्य के पैरा 7 में एवं अन्य। बनाम जसबीर कौर और अन्य।", यह हो चुका है यह माना गया कि अभिव्यक्ति "न्यायसंगत" दर्शाती है कि राशि न्यायसंगत होनी चाहिए, निष्पक्ष, तर्कसंगत और मनमाना नहीं। श्रीमती के पैरा 16 में। सारी "वर्नव एंड ऑर्स. बनाम। दिल्ली परिवहन निगम और अन्र. '2, इस अदालत ने कहा है कि मुआवजे का "एक उपहार, उदारता या लाभ का स्रोत होने का इरादा नहीं है। हालाँकि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है कि उचित मुआवजा कितनी राशि होगी।

16. आई. डी. 1 के मामले (उपरोक्त) में व्याख्या से स्पष्ट सिद्धांत यह है कि यदि राशि "मृतक के आश्रितों को देय होगी, अन्यथा भी", तो वही राशि 1988 के अधिनियम के तहत देय मुआवजे की राशि से कटौती योग्य नहीं होगी।साथ ही, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आय की हानि एक महत्वपूर्ण शीर्ष है जिसके तहत 1988 के अधिनियम के संदर्भ में मुआवजे का दावा किया जाता है।"आय के नुकसान" की मात्रा का घटक, अन्य बातों के साथ-साथ, "वेतन और मजदूरी" हो सकता है जो अन्यथा मृतक कर्मचारी द्वारा अर्जित किया जाता यदि वह मोटर दुर्घटना के कारण हुई चोट से बच जाता।तथापि, यदि नियोक्ता द्वारा मृतक कर्मचारी के आश्रितों को, जैसा कि 2006 के नियमों द्वारा पूर्वनिर्धारित किया गया है, उस ओर से मुआवजा दिया जाना था-मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता के रूप में अनुकंपा सहायता प्रदान करने के लिए, जिनकी मृत्यु हो जाती है, यह समझ से परे है कि आश्रितों को अभी भी 1988 के अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे को बनाए रखने के लिए उन्हें होने वाली आय की संभव या संभव हानि के रूप में उसी राशि का दावा करने की अनुमति दी जा सकती है।

17. 2006 के नियमों की योजना के अवलोकन से इस स्थिति को बल मिलेगा कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को विशिष्ट अवधि के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि के भुगतान के रूप में उचित रूप से मुआवजा दिया जाता है जो वेतन और अन्य भत्तों के बाद होता है जो अंतिम बार मृत कर्मचारी द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम में बिना कोई विशिष्ट दावा किए प्राप्त किए गए थे। यहाँ, हम 2006 के नियमों के पाठ का विज्ञापन कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैः

> "क्रमांक जीएसआर.19/कांस्ट./अनुच्छेद 309/2006-एलएन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान

करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं सेवा के दौरान/लापता सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सहायता, अर्थात्:-

(जोर दिया गया)

नियम 2 नियमों के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, अर्थात्, समूह सी और डी श्रेणी के एक मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार की सहायता करने के लिए, आकस्मिक स्थिति पर काबू पाने में जिसके परिणामस्वरूप नियमित सेवा में रहते हुए कमाने वाले को वित्तीय सहायता देकर नुकसान होता है।उक्त नियमों के नियम 3 में नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की गई है।नियम 4 के अनुसार, पात्र परिवार के सदस्यों को अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए फॉर्म ए में आवेदन जमा करना आवश्यक है।नियम 5 का कुछ महत्व है जो वित्तीय सहायता की सीमा का प्रावधान करता है।वही इस प्रकार पढ़ता हैः

"5.(1) किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर, कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में वेतन और अन्य भत्तों के बराबर राशि प्राप्त होती रहेगी जो अंतिम बार मृत कर्मचारी द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम में बिना कोई विशिष्ट दावा किए प्राप्त की गई थी।,-(क) कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए, यदि उसकी मृत्यु के समय कर्मचारी पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुका था; (ख) बारह वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक जब तक कर्मचारी बारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया होता।सेवानिवृत्ति की आयु, जो भी कम हो, यदि मृत्यु के समय

कर्मचारी की आयु पैंतीस वर्ष थी, लेकिन उसकी आयु अड़तालीस वर्ष नहीं हुई थी;

(ग) सात वर्ष है अवधि के लिए या उस तारीख तक कर्मचारी सेवानिवृत्ति है आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ होगा, जो भी कम हो, यदि कर्मचारी अड़तालीस वर्ष है आयु प्राप्त कर चुका हो।

(2) परिवार सामान्य नियमों के अनुसार उस अवधि के बाद ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसके दौरान उपरोक्त वित्तीय सहायता पूरी हो जाती है।

(3) एक मृत सरकारी कर्मचारी का मेंिवार, जो सरकारी आवास में कब्जा कर रहा है, मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सामान्य किराया/लाइसेंस शुल्क के भुगतान में निवास को बनाए रखना जारी रखेगा।कर्मचारी।

(4) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, कमाने वाले की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मृतक कर्मचारी के परिवार को पच्चीस हजार रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।

(5) सहायता की गणना के उद्देश्यों के लिए मकान किराया भत्ता भत्ते का हिस्सा नहीं होगा।"

18. नियम 6 अनुग्रह सहायता के लंबित मामलों से संबंधित है, जिनसे हम वर्तमान अपीलों में संबंधित नहीं हैं।लेकिन पुनर्कथन को पूरा करने के लिए, हम उक्त प्रावधान का उल्लेख कर सकते हैं।यह अभिनिर्धारित करता है कि अनुग्रह सहायता के

सभी लंबित मामलों को नए नियमों (2006 के i.e.Rules) के तहत शामिल किया जाएगा।इसके अलावा, अवधि की गणना और ऐसे मामलों में भुगतान नए नियमों की अधिसूचना की तारीख से किया जाएगा।इसके अलावा यह प्रावधान है कि परिवारों के पास नए नियमों के तहत प्रदान की जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता के बदले में नियम, 2003 या 2005 में प्रदान किए गए एकमुश्त अनुग्रह अनुदान का विकल्प होगा।

19. नियम 5 पर वापस लौटते हुए, उपखंड (I) उस अवधि के लिए प्रावधान करता है जिसके दौरान मृत कर्मचारी के आश्रितों को वेतन और अन्य भत्तों के बराबर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है जो मृत कर्मचारी द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम में बिना कोई विशिष्ट दावा किए प्राप्त की गई थी।उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि परिवार सामान्य नियमों के अनुसार उस अवधि के बाद ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा जब वे उप-नियम (1) के संदर्भ में वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे।उप-नियम (3) कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सरकारी निवास के मृत सरकारी कर्मचारी के मेंिवार को सामान्य किराया/लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की गारंटी देता है। उप-नियम (4) के आधार में, मृतक कर्मचारी के मेंिवार को 25,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है ताकि कमाने वाले की हानि में तत्काल जरूरतों को पूरा किया जा सके।उप-नियम (5) में स्पष्ट किया गया है कि घर का किराया भत्ता सहायता की गणना के उद्देश्यों के लिए मंजूरी का हिस्सा नहीं होगा।

20. नियम 5 मोटे तौर पर दो पहलुओं से संबंधित है।सबसे पहले, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन और अन्य भत्तों के नुकसान के लिए अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता प्रदान करके मृतक सरकारी कर्मचारी के वेतन की क्षतिपूर्ति करना।नियम 5 का दूसरा भाग मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को भत्ते और रियायतों के तरीके से क्षतिपूर्ति करना है-निर्दिष्ट शर्तों पर सरकारी निवास पर

कब्जा बनाए रखना, पारिवारिक पेंशन और अन्य भत्ता। जहाँ तक दूसरे भाग का संबंध है, यह अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है जो किसी भी तरह से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त की जाती है।1988 के अधिनियम के तहत न्यायसंगत मुआवजे के निर्धारण के लिए दावे की राशि से इसकी कटौती नहीं की जा सकती है।

21. दावेदार वैध रूप से 1988 के अधिनियम के तहत नियम 5 के पहले भाग के अंतर्गत आने वाली बीमा कंपनी के खिलाफ मृतक सरकारी कर्मचारी के "वेतन और मजदूरी" के नुकसान के लिए दावा करने के हकदार हैं।हालाँकि, मृतक सरकारी कर्मचारी (हरियाणा राज्य द्वारा नियोजित) के दावेदार या आश्रित, नियम 5 के पहले भाग-"वेतन और भत्ते" के तहत आने वाले उसी विषय के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, जो 2006 के नियमों के नियम 5 (1) के तहत नियोक्ता (राज्य) से उन्हें प्राप्त होते हैं।कि, यदि मृतक कर्मचारी मोटर दुर्घटना की चोट से बच जाता, तो वह रोजगार में रहता और अपने नियमित वेतन और भत्तों की कमाई करता। उक्त नियमों की कोई अन्य व्याख्या अनिवार्य रूप से मृत सरकारी कर्मचारी के "वेतन और मजदूरी" के नुकसान के लिए एक ही मद में दोगुना भुगतान करेगी, जिसमें आश्रितों/दावेदारों को बोनस, उदारता या लाभ के स्रोत का अनुदान शामिल होगा। कुछ इसी तरह की स्थिति बताई गई है मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 167 में, जो इस प्रकार है:

> "167. मुआवजे सीए दावों सीए संबंध में विकल्प सी एसईएस।- श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट इस अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावे को जन्म देती है और श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत भी, मुआवजे का हकदार व्यक्ति अध्याय X के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनमें से

किसी एक के तहत ऐसे मुआवजे का दावा कर सकता है।अधिनियम

लेकिन दोनों के तहत नहीं।"(जोर दिया गया)

22. वास्तव में, 2006 के नियमों के तहत प्राप्य दावे का समान वैधानिक बहिष्कार अनुपस्थिति है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दावा न्यायाधिकरण को इस तथ्य से अनजान रहना चाहिए कि मृतक के वेतन और मजदूरी के नुकसान के दावे को नियोक्ता द्वारा नियम 5 (1) के तहत अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता के रूप में पहले ही किया जा चुका है या किया जाएगा।दावा न्यायाधिकरण को दावे का न्यायनिर्णयन करना है और मुआवजे की राशि निर्धारित करनी है जो उसे उचित लगती है।इसलिए, आश्रितों द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में वेतन और भत्तों के लिए प्राप्त होने वाली राशि का भुगतान दूसरी बार दावेदारों को नहीं किया जा सकता है।यह सच है कि 2006 में नियम लागू होंगे यदि सरकारी कर्मचारी की प्राकृतिक मृत्यु में कारण भी मृत्यु हो जाती है।साथ ही, 2006 के नियम स्पष्ट रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को मृतक सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के कारण अपकृत्यकर्ता या बीमा कंपनी से समान राशि का दावा करने में सक्षम नहीं बनाते हैं। न्यायसंगत कलम निर्धारित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण ~:इसलिए, 1988 के अधिनियम के तहत देय राशि, 2006 के नियमों के तहत मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त या प्राप्य राशि को "वेतन और अन्य भत्तों" के बराबर वित्तीय सहायता के लिए बाहर करना है जो अंतिम बार मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त की गई थी।इसका मतलब यह नहीं है कि नियमों के नियम 5 (।) के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि या भुगतान, "आय की हानि" के शीर्ष के तहत कुल पात्रता है।जहाँ तक आय में वृद्धि और अन्य लाभों के नुकसान के दावे की बात है, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी दुर्घटना से बच गया था, तो भी वे 1988 के अधिनियम के तहत अपने दावे में आगे बढ़ सकते हैं।क्योंकि,

यह 2006 के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।इसी तरह, मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नियम 5 के उप-नियम (2) से उप-नियम (5) के संदर्भ में अन्य लाभ दिए गए हैं, जिनमें पारिवारिक पेंशन, जीवन बीमा, भविष्य निधि आदि शामिल हैं, जो अप्रभावित रहना चाहिए और कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो हेलेन सी.रेबेल्लो और पेट्रीसिया जीन महाजन के मामलों (उपरोक्त) में बताए गए सिद्धांत को लागू करते हुए मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को किसी भी तरह से भुगतान किया जाएगा।

23. एक प्रियोरी, अपीलकर्ताओं को केवल उस सीमा तक सफल होना चाहिए जो नियम 2006 के नियम 5 (1) के मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो निर्दिष्ट अवधि के लिए मृतक कर्मचारी के वेतन और मजदूरी के नुकसान के बराबर है।

24. चूंकि विचार के लिए कोई अन्य बिंदु उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अपीलों को ऊमें बताए गए हद तक आंशिक रूप से सफल होना चाहिए।25.तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील आंशिक रूप स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावाहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।